

# NEXT IAS

## दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

---

भारत में बैंकों का निजीकरण

---

[www.nextias.com](http://www.nextias.com)

## भारत में बैंकों का निजीकरण

### Context

- हाल ही में फिक्की फोरम में भाषण देते हुए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने भारत में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के चक्र से मुक्ति पाने के लिए बैंकों के निजीकरण को एक महत्वपूर्ण सुधार बताया।

### भारत में बैंकों के निजीकरण के बारे में

- निजीकरण से तात्पर्य किसी व्यवसाय या इकाई के स्वामित्व, संपत्ति या नियंत्रण को सरकार से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया से है।
- हाल के वर्षों में, भारत सरकार व्यापक आर्थिक सुधारों के भाग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के निजीकरण पर विचार कर रही है जिसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, शासन में सुधार करना और निजी पूंजी को आकर्षित करना है।
- हालाँकि, बैंक निजीकरण के आस-पास वाद-विवाद बहुत संकीर्ण है, जिसमें समर्थक और आलोचक दोनों ही अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं।
- सरकारी स्वामित्व वाले बैंक बैंकिंग वातावरण को स्थिरता और निश्चितता प्रदान करते हैं। उनकी भूमिका केवल लाभ कमाने से कहीं आगे तक विस्तारित है; वे आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन के स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं।
  - इसके विपरीत, निजी बैंक मुख्यतः लाभ के लिए कार्य करते हैं, जिसके कारण जोखिमपूर्ण व्यवहार और अल्पकालिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है।

### ऐतिहासिक संदर्भ

- भारत के बैंकिंग परिदृश्य में 1969 में बड़ा परिवर्तन आया जब सरकार ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इसके बाद 1980 में छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- इसने इस क्षेत्र को परिवर्तित कर दिया, इसे अधिक समावेशी बना दिया और कृषि, रोजगार तथा ग्रामीण विकास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया।
- भारत ने 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों के दौरान निजीकरण की अपनी यात्रा शुरू की, जिसे 'नई आर्थिक नीति' या LPG(उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) नीति के रूप में जाना जाता है।
- PSBs भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गए, जिन्होंने संवृद्धि, विकास और वित्तीय समावेशन का समर्थन किया।

### नीतिगत विचार

- नरसिंहम समिति-I (1991):** इसकी स्थापना भारत में आर्थिक संकट के समय की गई थी। इसकी सिफारिशों का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करना था, जिसमें सम्मिलित हैं:

- भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए 4-स्तरीय पदानुक्रम बनाना, जिसमें शीर्ष पर प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सबसे नीचे ग्रामीण विकास बैंक होंगे।
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी के लिए RBI के तहत एक अर्ध-स्वायत्त निकाय की स्थापना करना।
- ब्याज दरों को विनियमित करना और बैंकों के खातों का पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करना।
- परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि की स्थापना करना।
- **नरसिंहम समिति-II (1998) (जिसे बैंकिंग क्षेत्र समिति के नाम से भी जाना जाता है):** इसने सुधारों की प्रगति की समीक्षा की तथा आगे सुदृढ़ीकरण के उपाय प्रस्तावित किए:
  - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की सिफारिश की।
  - उच्च NPAs वाले बैंकों के लिए "संकीर्ण बैंकिंग" की अवधारणा प्रस्तुत की, जिससे उन्हें अल्पकालिक और जोखिम-मुक्त परिसंपत्तियों में निवेश करने की अनुमति मिली।
  - एक नियामक के रूप में RBI की भूमिका में सुधारों का समर्थन किया।

### निजीकरण के लिए हालिया प्रयास

- **लाभप्रदता और समेकन:** पिछले कुछ वर्षों में, समेकन के विभिन्न दौरों के परिणामस्वरूप कम लेकिन बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बने हैं। ये बैंक लाभदायक हो गए हैं, जिससे नीति निर्माताओं को निजीकरण पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया है। इसका लक्ष्य एक कम खर्चीली, अधिक कुशल बैंकिंग प्रणाली का निर्माण करना है।
- **समान विकास:** राष्ट्रीयकृत बैंकों ने समान क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उपेक्षित क्षेत्रों में सेवाएँ विस्तारित हुई हैं। ग्रामीण शाखाओं में वृद्धि हुई, जिससे साहूकारों पर निर्भरता कम हुई।
  - इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हरित, नीली और डेयरी क्रांतियों को समर्थन दिया तथा बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

### हालिया विकास

- **निजीकरण की योजनाएँ (2021):** वित्त वर्ष 2021-2022 के केंद्रीय बजट में, कम प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने, ऋणदाताओं को स्वायत्तता प्रदान करने और बैंकिंग तथा NBFC क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की घोषणा की गई थी। हालाँकि, निजीकरण के लिए विशिष्ट बैंकों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
- **RBI की सिफारिशों की स्वीकृति (2021):** एक आंतरिक कार्य समूह ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और कॉर्पोरेट संरचना पर सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

- RBI ने 33 में से 21 सिफ़ारिशें स्वीकार कर लीं, जिनमें 15 वर्षों में प्रमोटरों की हिस्सेदारी की सीमा 15% से बढ़ाकर 26% करना सम्मिलित है। समूह ने प्रवर्तक संस्थाओं पर उपयुक्त तथा उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र का भी सुझाव दिया।

### बैंक निजीकरण के पक्ष में तर्क

- **दक्षता और लाभप्रदता:** निजी बैंकों को अधिक लाभ-उन्मुख और सक्रिय माना जाता है, जिससे बेहतर प्रबंधन पद्धतियां, सुव्यवस्थित परिचालन और बेहतर वित्तीय प्रदर्शन हो सकता है।
  - हालांकि, यह पहचानना आवश्यक है कि सार्वजनिक बैंक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पहले से वंचित क्षेत्रों, सेक्टरों और हाशिए पर पड़े समूहों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाते हैं।
  - जबकि निजी बैंक शुद्ध लाभप्रदता के मामले में अधिक कुशल लग सकते हैं, वित्तीय समावेशन संकेतकों पर विचार करने पर सार्वजनिक बैंक बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
- **सरकार का एकाधिकार:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में सरकार का स्वामित्व बैंकिंग परिसंपत्तियों का लगभग 70% है। इससे एक तरह का आभासी एकाधिकार उत्पन्न हो गया है और इसलिए प्रतिस्पर्धा तथा अकुशलता कम हो गई है।
- **पिछला अनुभव:** रणनीतिक विनिवेश से समग्र दक्षता लाभ में वृद्धि हुई है, जो बाद में शेयरधारकों के लिए उच्च रिटर्न में परिवर्तित हो गई। DBT, मनरेगा मजदूरी, प्रधानमंत्री जन धन योजना आदि जैसे सामाजिक कारणों के लिए MFIs और NPBs का लाभ प्राप्ति की संभावना।
- **सरकारी कोष पर कम भार:** उच्च बेसल III आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए उनके पुनर्पूजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करके सरकार पर भार कम करें।

### बैंक निजीकरण के विरुद्ध तर्क

- **एकाधिकार संबंधी चिंताएँ:** निजीकरण से संकेन्द्रण, गुटबाजी और प्रतिस्पर्धा में कमी आ सकती है। सभी के लिए किफायती बैंकिंग सेवाएँ सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है।
  - हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लाभ से परे एक व्यापक सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। वे कमजोर वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की सहायता करते हैं।
- **वित्तीय बहिष्कार:** जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का निजीकरण किया जाता है, तो यह जोखिम होता है कि निजी बैंक ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों की उपेक्षा करते हुए, लाभदायक शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दूरदराज और हाशिए पर पड़े समुदायों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में PSB ने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** निजीकरण PSB जमाराशियों के पीछे संप्रभु गारंटी को हटा देता है। कुछ लोगों को चिंता है कि इससे घरेलू बचत कम सुरक्षित हो सकती है। जब लोग PSB में पैसा

जमा करते हैं, तो वे प्रायः सरकार के समर्थन पर विश्वास करते हैं। निजीकरण उस विश्वास को समाप्त कर सकता है।

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की कम रिपोर्टिंग:** अतीत में, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा NPA की कम रिपोर्टिंग के उदाहरण सामने आए हैं। आलोचकों का तर्क है कि निजीकरण इसे बढ़ा सकता है, क्योंकि निजी बैंकों को अपनी छवि और शेयर की कीमतों को बनाए रखने के लिए NPA को कम दिखाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।
- **एकाधिकार और व्यवसायी समूहन जोखिम:** निजीकरण बैंकिंग शक्ति को कुछ निजी संस्थाओं के हाथों में केंद्रित करता है। आलोचकों को भय है कि इससे एकाधिकारवादी व्यवहार और व्यवसायी समूहन को बढ़ावा मिल सकता है। प्रतिस्पर्धा की कमी से उपभोक्ताओं को हानि हो सकती है क्योंकि इससे उनके पास विकल्प सीमित हो सकते हैं और संभावित रूप से शुल्क और प्रभार बढ़ सकते हैं।

### केस स्टडी: अमेरिका में बैंक विफलताएं

- यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, जहां निजी बैंकों का प्रभुत्व है, विफलताएं असामान्य नहीं हैं। 2023 में, विभिन्न महत्वपूर्ण बैंक बंद हो गए।
- यह पैटर्न दशकों से जारी है, जिससे सैकड़ों निजी बैंक प्रभावित हुए हैं। पनगढ़िया ने भारत के लिए जिस स्वामित्व मॉडल की सिफारिश की है - निजीकरण - वह अन्य जगहों पर बार-बार विफल रहा है।

### निष्कर्ष और आगे की राह

- **चयनात्मक दृष्टिकोण:** सरकार की प्रस्तावित योजना छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर केंद्रित है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंक सम्मिलित नहीं हैं। इस लक्षित दृष्टिकोण का उद्देश्य दक्षता लाभ को सामाजिक उद्देश्यों के साथ संतुलित करना है।
- **नियामक सतर्कता:** स्वामित्व के बावजूद, मजबूत नियामक निरीक्षण महत्वपूर्ण बना हुआ है। RBI को स्थिरता, पारदर्शिता और विवेकपूर्ण ऋण देने की प्रथाओं को सुनिश्चित करना जारी रखना चाहिए।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** शायद एक हाइब्रिड मॉडल - जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दक्षता के लिए निजी खिलाड़ियों के साथ भागीदारी करते हुए अपने सामाजिक जनादेश को बनाए रखते हैं - पर विचार किया जा सकता है।
- **सुधार और स्थिरता को संतुलित करना:** NPAs को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक स्थिर बैंकिंग प्रणाली को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को पूरी तरह से निजीकरण किए बिना सुधारा जा सकता है।
  - दक्षता, जवाबदेही और सार्वजनिक हित के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

- भारत में बैंकों का निजीकरण एक कठिन कार्य है। दक्षता, सामाजिक जिम्मेदारी और वित्तीय स्थिरता के बीच सही संतुलन बनाना आवश्यक है।

Source: BL



### दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

**प्रश्न.** भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में परिवर्तन लाने में निजीकरण की भूमिका का विश्लेषण करें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किस तरह से सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों के अनुरूप है। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ चर्चा करें।

